International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

वर्तमान दौर में 'कृषि लागत' की वृद्धि और लाभ में कमी: एक नूतन विमर्श

डॉ. महेन्द्र यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद

भारतीय अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं विद्यमान हैं। लेकिन वर्तमान में किसानों की आत्महत्या की समस्या देश की एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, जो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है, बल्कि मानव विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में बनी हुं है। भारत की 70 प्रतिशत किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ी है, परन्तु यह तथ्य भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में किसान रोजाना 'आत्महत्या' के शिकार हो रहे हैं। यह घटनाएं वर्ष 2017 में अपने क्रम में वृद्धि कर रही हैं। वर्ष 2017 के संसद के मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को संसद कार्यवाही के केन्द्र में रखा गया। परन्तु यह किसानों की समस्या का हल नहीं है। स्वतंत्र भारत के पश्चात एक दीर्घ अवधि व्यतीत करने के बाद भी किसानों की दशा में केवल नाम मात्र का ही अन्तर दृष्टिगत होता है, जिसे अंगुलियों पर आसानी से गिना जा सकता है। ऐसी कौन–सी समस्याएं हैं जो किसानों की सुदृढ़ स्थिति का सपना कभी पूरा नहीं होने देते हैं।

भारतीय किसानों की समस्याएं अथवा बाधायें

देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और वह कृषि पर ही निर्भर हैं ऐसे में किसानों की खुशहाली की बात सभी (सरकार, पंचायती शासन व्यवस्था, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक संस्थाएं) करते है और उनके लिये योजनाएं भी बनाते हैं, किन्तु उनकी मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैः जैसे– भारत के कृषि जगत में कृषि शिक्षा के विश्वविद्यालय और कॉलेज नाम–मात्र के हैं, उनमें भी गुणवत्तापरक शिक्षा का अभाव है, शोध संस्थानों का पूर्णतया अभाव है, गुणवत्तापरक शिक्षकों का अभाव है, जिसके कारण

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

कृषि में होने वाले क्रान्तिकारी परिवर्तनों का प्रयास सफल हो ही नहीं पाता है। इसके साथ ही सिंचाई, बीज, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में नवाचार की अनुपस्थिति रहती है।

भूमि एवं फसल प्रबन्धन की समस्या

स्वतंत्रता के पश्चात भूमि जोतों का निर्धारण तो हुआ (चकबन्दी, हदबन्दी आदि) परन्तु भूमि एवं फसल प्रबन्धन के विषय पर कभी भी चर्चा को महत्व नहीं दिया गया। इसके साथ तदर्थ आधार पर यदि नीतियों का निर्धारण किया भी जाता है तो निर्धारक ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें इस क्षेत्र की कोई जानकारी भी नहीं होती। राष्ट्रीय स्तर पर यह नीति बनाई जानी चाहिए कि देश के अन्दर विभिन्न जिंसों की कितनी खपत है और वह किस क्षेत्र में है, इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए कितने भण्डारण की आवश्यकता है?

भूमि अधिग्रहण नीति

केन्द्र/राज्य सरकारों अथवा राज्यान्तर्गत गठित विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण की नीति में कृषि योग्य भूमि के मद्देनजर परिवर्तन किया जाना परमावश्यक है। औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना विकास व आवासीय योजनाओं हेतु ऐसी भूमि का अधिकरण किया जाना चाहिए जो कृषि योग्य नहीं है। आवासीय औद्योगिक एवं ढांचागत निर्माणों के लिये कृषि योग्य भूमि अत्यधिक संकुचित होती चली जायेगी जो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण–पोषण हेतु कृषि उत्पादन के लिए अपर्याप्त हो रही है।

साख प्रबन्धन/ऋण की समस्या

'किसान आत्महत्या' घटनाक्रम का प्रमुख कारण साख व्यवस्था दो प्रकार की होती है–अल्पाकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार का विशेष ध्यान रहता है, परन्तु दीर्घकालीन ऋणों में किसान की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋणों की ब्याज दरें अल्पकालीन ऋण की तुलना में अधिक हैं। परियोजना आधारित ऋण वितरित किया जाता है लेकिन किसान की अन्य

आवश्यकताओं के लिए ऋणों का कोई प्रावधान दीर्घकालीन व्यवस्था में नहीं है। इसी के साथ साहुकारों के ऋण दुष्चक्र की व्यवस्थाओं से आप भली–भांति परिचित हैं।

क्रय–विक्रय की समस्या

किसानों की प्रमुख समस्या क्रय–विक्र की समस्या भी है जब कृषि बाजार में आता है तो उसके मूल्य निरन्तर गिरने लगते हैं। मध्यस्थ सस्ती दरों पर उसका माल क्रय कर लेते हैं जिससे कृषि घाटे का व्यवसाय बना हुआ है। दुर्भाग्य है कि सम्बन्धित लोग औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन की दरें लागत, मांग और पूर्ति ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं। किन्तु किसान की जिंसों का मूल्य या तो सरकार या क्रेता द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसमें भी तत्काल नष्ट होने वाले उत्पाद की बिक्री के समय किसान असहाय दिखाई देता है। उत्पाद मूल्य के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए सूचना विभाग भी जिम्मेदार है। वर्तमान समय में किसानों के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो यह तय कर सके कि उसके उत्पाद का उचित मूल्य किस बाजार में क्या है और भविष्य में मूल्य घटने–बढ़ने की क्या सम्भावनाएं हैं।

सरकारी योजनाओं में तकनीकी दांव–पेच

किसानों की समस्या के विषय जब 'लोन' एवं 'किसान डिफाल्टर' की बात की जाती है एवं इससे आहत होकर किसान आत्महत्या कर लेता है, यह सरकारी योजनाओं की विफलता है। सरकारी योजनाओं में इस कदर तकनीकी दांव–पेच है वह इसे समझ ही नहीं पाता है। जैसे–यदि किसान को ऋण दिया जाता है तो पहले उसका फसल बीमा होगा ऐसे में किसान डिफाल्टर कैसे होगा? अगर फसल बर्बाद होती है तो ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व बीमा कम्पनियों का होगा।

उपरोक्त के अलावा समस्या यह भी है कि बैंक योजनाओं को लेकर किसानों तक नहीं पहुंच पाते एवं ऐसे में किसान बिचौलियों के चुंगल में फंस जाते हैं।

असफल कृषि कल्याण योजनाएं

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

आत्महत्या किसानों को कृषि समस्याओं से निजात पाने का एकमात्र उपाय दिखाई पड़ रहा है जोकि किसी भी देश का अन्धकारमय पहलू है। हालांकि कृषि एवं किसानों की समस्याओं को हल करने लिये महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाई गई हैं परन्तु वह भी अपने लक्ष्यों में पूर्ण रूप में सफल नहीं है; जैसे

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे–जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, पानी का अपव्यय कम करना तथा सतत जल संरक्षण आदि।

कृषि ऋण योजना

इस योजना के तहत विविध ऋण योजनाओं की सुविधायें किसानों को दी जाती हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऋणों में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण बैंक की स्थापना भी इसी योजना के उद्देश्य से की गई थी। योजना के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को ऋण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई–नाम) योजना

वर्ष 2015 में किसानों को उनकी उपज के अच्छे मूल्य प्राप्त कराने के लिये इस योजना का शुभारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य मार्च, 2018 तक देश की 585 नियन्त्रित मण्डियों को सामान्य ई–मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है।

परम्परागत कृषि विकास योजना

वर्ष 2015 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना का शुभारम्भ किया गया है, इस योजना के तहत मनरेगा के अन्तर्गत जैविक खाद के लिये 10 लाख वानस्पतिक खाद्य की दवाइयां तैयार की गई हैं। नीम कोटेड यूरिया भी इसी योजना का भाग है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

योजनाओं को सफल बनाने की सम्भावनाएं

निम्नस्तर से यदि प्रारम्भ करें तो कृषि शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए और प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। कृषि संस्थानों को ऐसे बीजों की खोज करनी चाहिए जिनकी उत्पादकता अधिक हो, परन्तु किसानों को प्रत्येक बाजार से नये बीज नहीं खरीदने पड़े एवं किसान अपने पास अगली फसल के लिए बीज का भी सुरक्षित भण्डार भी कर सकें। भूमि एवं फसल प्रबन्धन हेतु, जिंसवार उत्पादन की व्यवस्था क्षेत्रीय आधार पर करनी चाहिए एवं सम्बन्धित किसानों को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। किसानों हेतु अच्छी प्रजाति के बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो खेत चिन्हित किये जायें, उन्हें ये बीज उपलब्ध कराये जाने चाहिए। फसल की बुवाई के समय कृषि क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ अपनी देख–रेख में बुवाई करायें तथा उन पर होने वाली बीमारियों, आवश्यक उर्वरकों, सिंचाई, निराई, गुड़ाई आदि कार्य आवश्यकतानुसार समय–समय पर कृषि विशेषज्ञों के निर्देशन में कराया जाये। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसान भी व्यावहारिक दृष्टि से प्रशिक्षित होंगे। किसानों की समस्या व्यक्तिगत स्तर से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है अतः इसके लिये स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। न्याय पंचायत अथवा ग्रामसभा स्तर पर एक कृषि केन्द्र होना चाहिए, जहां ग्रामीण कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित आवासीय सुविधाओं के साथ कार्यालय में कार्य कर सकें। यहां एक सहकारी समिति भी होनी चाहिए अथवा कृषि सहकारी समिति का विक्रय केन्द्र होना चाहिए जिस पर कृषि मानकों के अनुरूप बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की व्यवस्था कराई जाये, जो किसानों को ऋण के रूप में उपलब्ध हो। कृषि में जो भी फसल बोई जायें, उस फसल को सहकारी समिति के माध्यम से बीमाकृत कराया जाये।

यदि उल्लेखित सभी बिन्दुओं को कृषि क्षेत्र में अपना लिया जाता है तो वह दिन दूर नहीं होगा जब 'किसान की आत्महत्या' की खबर नहीं, बल्कि 'किसान विकास' की खबरें प्रकाश

में होंगी। हालांकि सरकार की ओर से कुछ प्रयास भी किये जा रहे हैं जिनका विस्तार आगे है। इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है कि सरकारी योजनायें असफल हो रही हैं।

References

Adam Cagliarini and Anthony Rush (June 2011). "Bulletin: Economic Development and Agriculture in India"

Central Institute of Fisheries Technology, India. 2008. Archived from the original on 1 July 2013.

Dahl, Robert, (1989). Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press.

Anthony Downs, (1957). An Economic Theory of Democracy. Harpercollins College.

"Handbook of Statistics on Indian Economy". Reserve Bank of India: India's Central Bank. 2011.

Department Of Elementary Education, National Council Of Educational Research And Training (2013), "Quality Management In Elementary Education Under SSA"

Lal, R. (August 2001). "Thematic evolution of ISTRO: transition in scientific issues and research focus from 1955 to 2000". Soil and Tillage Research. 61 (1–2): 3–12 [3].

Iqtidar Husain Siddiqui, "Water Works and Irrigation System in India during Pre-Mughal Times", Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 29, No. 1 (Feb., 1986), pp. 52–77.

"Brief history of wheat improvement in India". Directorate of Wheat Research, ICAR India. 2011

"PM Modi: Target to double farmers' income by 2022", The Indian Express, 28 February 2016

Das, A. (2011), Farmers' suicide in India: implications for public mental health, International Journal of Social Psychiatry, 57(1), 21–29

Staff, India Brand Equity Foundation Agriculture and Food in India Accessed 7 May 2013

"Rapid growth of select Asian economies". Food and Agriculture Organisation of the United Nations. 2009.

Chauhan, Chetan (1 April 2014). "UN climate panel warns India of severe food, water shortage". www.hindustantimes.com. Hindustan Times. Retrieved 31 March 2014

National Water Development Agency Ministry of Water Resources, Govt of India (2014)

Planning Commission of India (2002). *Tenth Five Year Plan.*

Planning Commission of India (2002). *Economic Survey*

Schurman, R. (2013), Shadow space: suicides and the predicament of rural India, Journal of Peasant Studies, 40(3), 597–601

Gruère, G. & Sengupta, D. (2011), Bt cotton and farmer suicides in India: an evidence-based assessment, The Journal of Development Studies, 47(2), 316–337

Sankaran, S. "28". Indian Economy: Problems, Policies and Development. pp. 492–493